भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †789

दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ

संपत्तियों का मानचित्रण

†789. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गांवों में ड्रोन द्वारा संपत्तियों के मानचित्रण का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;
(ख) इस योजना के माध्यम से किसानों को किस प्रकार का लाभ मिला है;
(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2015 से लेकर अब तक इस हेतु वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;
(घ) क्या मेघालय और उत्तर प्रदेश राज्य में स्वामित्व योजना लागू की जा रही है और यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से लेकर अब तक इस हेतु प्रत्येक वर्ष स्वीकृत राशि सहित हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार स्वामित्व योजना की जगह किसी वैकल्पिक योजना का विचार रखती है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई), राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में जहां संपत्तियों की मैपिंग ड्रोन द्वारा की गई है, उन गांवों का राज्य-वार प्रतिशत **अनुबंध** I में संलग्न है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की योजना "स्वामित्व" का उद्देश्य गांवों में आबाद क्षेत्रों (आबादी) में घर वाले ग्रामीण परिवारों के गृहस्वामियों को 'हक़-विलेख' प्रदान करना है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों के ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भू-खंडों का सर्वेक्षण किया जाता है। यह संपत्तियों के स्पष्ट स्वामित्व के

निर्धारण में मदद करता है। यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है जिससे बैंक ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है, संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आती है, व्यापक रूप से ग्रामीण स्तर की योजना की आयोजना और संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिए एक आधार प्रदान करता है, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होता है जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है।

(ग) योजना के तहत, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) को धनराशि दो घटकों - ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है । सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों के आधार पर राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए राज्यों को सीमित पैमाने पर निधियां भी सीधे जारी की जाती हैं। योजना के तहत अब तक जारी की गई राशि का विवरण **अनुबंध** II में दिया गया है।

(घ) स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की जा रही है। मेघालय राज्य ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश के 90,904 गाँवों में से 75 जिलों के 90,446 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 33,642 गांवों के लिए लगभग 49.8 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इस योजना के तहत, सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों के आधार पर राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए राज्यों को सीमित पैमाने पर सीधे धनराशि भी जारी की जाती है। आईईसी और एसपीएमयू घटकों के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश राज्य को वितिय वर्ष 2020-21 में 1.44 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। यह योजना कार्यान्वयनाधीन है और सरकार ने स्वामित्व योजना की कोई वैकल्पिक योजना प्रस्तावित नहीं की है।

***

अनुबंध I

'सम्पतियों के मानचित्रण' के संबंध में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्षित गांव	ड्रोन उड़ान पूरी हुई	ड्रोन उड़ाने पूरा होने का %
1	आंध्र प्रदेश	17949	4577	25.50%
2	अरुणाचल प्रदेश	5484	1190	21.70%
3	असम	1074	630	58.66%
4	छत्तीसगढ	18500	5966	32.25%
5	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	80	80	100.00%
5	दिल्ली	31	31	100.00%
6	गुजरात	13132	5324	40.54%
7	हरयाणा	6260	6260	100.00%
8	हिमाचल प्रदेश	21253	3091	14.54%
9	जम्मू और कश्मीर	4590	1439	31.35%
10	झारखंड	757	240	31.70%
11	कर्नाटक	30715	2972	9.68%
12	केरल	1666	107	6.42%
13	लद्दाख	243	173	71.19%
14	लक्षद्वीप समूह	10	10	100.00%
15	मध्य प्रदेश	43136	43133	99.99%
16	महाराष्ट्र	39733	33780	85.02%
17	मणिपुर	3856	53	1.37%
18	मिजोरम	864	88	10.19%
19	ओडिशा	3356	1785	53.19%
20	पांडिचेरी	96	96	100.00%
21	पंजाब	12782	4312	33.73%
22	राजस्थान	46767	10412	22.26%
23	सिक्किम	1	1	100.00%
24	तमिलनाडु	2	2	100.00%
25	तेलंगाना	5	5	100.00%
26	त्रिपुरा	898	3	0.33%
27	उत्तर प्रदेश	90904	90446	99.50%
28	उत्तराखंड	7441	7441	100.00%
29	गोवा	410	410	100.00%
31	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	186	186	100.00%
	कुल	**372181***	**224243**	60.25%

* योजना के कार्यान्वयन के दौरान गाँवों की कुल संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध II

'सम्पतियों के मानचित्रण' के संबंध में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वामित्व योजना के अंतर्गत निधियों का वर्षवार आवंटन (राशि रुपये करोड़ में)				
	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
जारी की गई कुल धनराशि	79.65	140.0	97.2*	316.84

* दिनांक 03.02.2023 की स्थिति के अनुसार।